



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 8, 1991/वैशाख 18, 1913

No. 16]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 8, 1991/VAISAKHA 18, 1913

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 1991

स. 1 पीएसबी/स्टाक/ओएसआर/1991 — बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों  
का अंर्जन और अन्तर्गण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) के खण्ड  
19 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की  
सलाह एवं केन्द्रीय सरकार की पूर्ण स्वीकृति से पंजाब एण्ड सिंध बैंक के  
निदेशक मंडल के सदस्य एतद्वारा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी)  
सेवा विनियम-1982 में संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाते हैं।

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :-

(1) इन विनियमों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा  
(संशोधन) विनियम, 1991 कहा जाएगा।

(2) यह विनियम सरकारी गैजट में प्रकाशन की तिथि से लागू  
होगे।

विनियम-21 निम्नानुसार संशोधित है —

(21) दिनांक 1-11-1987 को तथा उसके बाद से महंगाई भत्ता  
योजना निम्नानुसार होगी :-

(1) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग  
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960-  
100 की तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर 4  
अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से देय  
होगी।

(2) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरो पर देय होगा —

- (1) रु. 2500/- तक वेतन का 0.67%, और
- (2) रु. 2500/- से ऊपर परन्तु रु. 4000/- तक वेतन  
का 0.55%, और
- (3) रु. 4000/- से ऊपर परन्तु रु. 4260/- तक वेतन  
का 0.33%, और
- (4) रु. 4260/- से ऊपर वेतन का 0.17%

विनियम-22 (2) और विनियम 22(3) के स्पष्टीकरण । (1)  
और स्पष्टीकरण 2 निम्नानुसार संशोधित है :—

22(2) 1-1-1990 को और उसके बाद में, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा मकान नहीं दिया गया है, तो वह निम्नलिखित शर्तों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :—

स्तंभ-1	स्तंभ-2
कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1) सरकार के मार्गनिर्देश के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख "ए" श्रेणी के नगर तथा समूह "ए" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 14% परन्तु अधिकतम रु. 450/- प्र. मा.
(2) क्षेत्र-1 में ग्रन्थ स्थान तथा समूह "बी" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12% परन्तु अधिकतम रु. 375/- प्र. मा.
(3) क्षेत्र 2 तथा (उपयुक्त) 1 तथा (2) के अन्तर्गत न आने वाले राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियाँ	वेतन का 10% परन्तु अधिकतम रु. 325/- प्र. मा.,
(4) क्षेत्र-3	वेतन का 8% परन्तु अधिकतम रु. 300/- प्र. मा.

परन्तु यदि कोई अधिकारी किराए की रमीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रवर्ग के 6 प्रतिशत से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया अथवा स्तंभ-2 में उल्लिखित शर्तों पर, जो भी कम हो अन्यथा देय अधिकतम मकान किराया भत्ते का अधिक से अधिक 175% होगा।

स्पष्टीकरण :—

- (1) (ख) दिनांक 1-4-1990 को या उसके बाद में यदि नियास स्थान बैंक द्वारा किराए पर लिया गया है तो बैंक द्वारा देय संविदागत किराया अथवा ऊपर "क" में दर्शाई गई पद्धति के अनुसार आका गया किराया, जो भी कम हो ।
- (2) इस विनियम और विनियम-23 में क्षेत्र-1, क्षेत्र-2 तथा क्षेत्र-3 का अर्थ निम्नानुसार होगा :—
 

क्षेत्र-1 —	12 लाख से अधिक जन संख्या वाले स्थान ।
क्षेत्र-2 —	क्षेत्र-1 में न आने वाले ऐसे सभी शहर जिनकी जन-संख्या 1 लाख और उससे अधिक हो ।
क्षेत्र-3 —	क्षेत्र-1 और क्षेत्र-2 में न आने वाले अन्य सभी स्थान ।

विनियम-24 निम्नानुसार संशोधित है :—

विनियम 24

- (1) अधिकारी अपने और अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात् :—

(क) चिकित्सा व्यय :—

1-1-90 को और उसके बाद में अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सीधे स्तंभ-1 में विनिर्दिष्ट वेतन सीमा तथा

स्तंभ-2 में विनिर्दिष्ट प्रतिपूर्ति सीमा के अन्वये की जाएगी । इसके लिए अधिकारी की अपनी ओर से ही प्रमाणपत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और बाका की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा ।

सारणी	
वेतन सीमा	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
1	2
रु. 2100/- से . 3060/-	रु. 750/-
रु. 3061/- प्र. मा. और अधिक	रु. 1000/-

टिप्पणी : उपरोक्त में न आई चिकित्सा गृहयुता राशि की अधिकारी संचित कर सकता है परन्तु संचित राशि किसी भी समय उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :—

इस विनियम के प्रयोजन के लिए, अधिकारी के परिवार में उसका पति/ उसकी पत्नी, पूर्णतः आश्रित संतान और पूर्णतः आश्रित माता-पिता ही शामिल होंगे ।

(ख) अस्पताल में भर्ती खर्च :—

- (1) दिनांक 1-4-1989 को और उसके बाद से ऐसे सभी मामलों में जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो, अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकारी के मामले में 90% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60% तक के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी । किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति मिल, बाऊजर आदि के आधार पर सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत की जाएगी ।
- (2) अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों से, यथास्थिति, यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी सरकारी या नगर पालिका अस्पताल में या किसी निजी अस्पताल (अर्थात् किसी खास, धर्मार्थ संस्थान या सामिक मिशन के प्रबंध के अधीन आने वाले अस्पतालों में भर्ती हों, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारीगण या उनके परिवार के सदस्य अथवा दोनों किसी अनुमोदित निजी नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं किन्तु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति अर्पण वर्णित अस्पतालों में भर्ती पर प्रतिपूर्ति योग्य राशि तक सीमित रहेगी ।
- (3) 1-4-1989 को और उसके बाद से भाग्यताप्राप्त अस्पताल के अधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा घर पर इलाज की आवश्यकता प्रमाणित करने पर निम्नलिखित रोगों के चिकित्सा खर्चों को भी अस्पताल में भर्ती खर्च माना जाएगा और उसने संबंधित चिकित्सा खर्चों की अधिकारी के मामले में 90% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

कैंसर, तपेदिक, पक्षाघात, हृदय रोग, दूधमर, चेबक, लूरेमी, बिपथीरिया, कुष्ठरोग, गुर्दे की खराबी ।

विनियम 33(4) निम्नानुसार संशोधित है :—

विनियम 33(4) 1-1-1990 को और उसके बाद से, जब तक कि भावदित छुट्टी नामजूर ना कर दी गई हो, विशेषाधिकार छुट्टी, अधिक से अधिक 240 दिनों तक संचित की

दिनांक 1-1-1987 से विनियम 41(4) (ब) निम्नानुसार संशोधित है :-

(ब) सभी निरीक्षण अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर निरीक्षण ह्यूटो पर बिराम के प्रतिदिन के लिए रु. 10/- का अनुपूर्वक दैनिक भत्ता दिया जा सकता है।

एन. एम. गुजराल,

उप महा प्रबन्धक (कार्मिक)

PUNJAB & SIND BANK

(Personnel Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 1991

No. PSB/Staff/OSR/1991.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Punjab & Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Punjab & Sind Bank (Officers) Service Regulations 1982.

Short title and Commencement:

- (i) These regulations may be called the Punjab & Sind Bank (Officers) Service (Amendment) Regulations, 1991.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

Regulation 21 stands amended as under:

REG. 21—On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under:—

- (i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) base 1960 = 100.
- (ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates:—
  - (i) 0.67% of 'Pay' upto Rs. 2500/- plus,
  - (ii) 0.55% of 'Pay' above Rs. 2500 to Rs. 4000 plus,
  - (iii) 0.33% of 'Pay' above Rs. 4000 to Rs. 4260 plus,
  - (iv) 0.17% of 'Pay' above Rs. 4260.

Regulation 22 (2) and Explanation 1(b) and Explanation (2) under Regulation 22 (3) stands amended as under:—

REG. On and from 1-1-1990, where an officer is not provided 22(2) any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates:—

Column-I	Column-II
Where the place of work is in	HRA Payable shall be
(i) Major 'A' class cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Govt. & Project Area Centres in Group 'A'	14% of the pay subject to a maximum of Rs. 450 p.m.
(ii) Other places in Area-I and Project Area Centres in Group	12% of the pay subject to a maximum of Rs. 375

(iii) Area-II and state capitals and capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) Above 10% of the pay subject to a maximum of Rs. 325 p.m.

(iv) Area-III 8% of the pay subject to a maximum of Rs. 300 p.m.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or at the rates indicated in Column II with a maximum of 175% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise, whichever is lower.

Explanation:

With effect from 1-4-1990.

1(b) where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure in (a) above, whichever is lower.

(2) In this Regulation and in Regulation 23 Area-I, Area-II, and Area-III shall mean as under:—

Area-I —Places with a population of more than 22 lakhs

Area-II —All cities other than those included in Area I which have a population of 1 lakh and more.

Area-III —All places not included in Area I and Area II.

Regulation 24 stands amended as under:

Reg. 24 (1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely:—

(a) Medical Expenses:

On and from 1-1-1990 reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in Column I of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in Column 2 thereof:

TABLE

Pay Range	Reimbursement limit p.a.
1	2
Rs. 2100 to Rs. 3060 p.m.	Rs. 750
Rs. 3061 p.m. and above	Rs. 1000

Note: An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Explanation:

"FAMILY" of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses:

(i) On and from 1-4-1989, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 90% in the case of an

officer and 60% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc). of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the government.

- (ii) The officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital i.e. hospitals under the management of a Trust, Charitable Institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

- (iii) On and from 1-4-1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domi-

ciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90% in case of an officer and 60% in the case of his family members: —

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumor, Small Pox, Pleurosy, Diphtheria, Leprosy, Kidney Ailment.

Regulations 33 (4) stands amended as under:

- REG. 33(4) On and from 1-1-1990 privilege leave may be accumulated upto not more than 240 days except where leave has been applied for and it has been refused.

Regulation 41 (4) (f) stands amended w.e.f. 1-1-1987 as under:

- (f) A supplementary Diem Allowance of Rs. 10/- per day of halt outside head quarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

N.S. GUJRAL, Dy. Gen. Manager (Personnel)